निर्भर करते हैं घड़ियों के पुर्जे देश में उपलब्ध साधनों से ही सप्लाई करने की व्यवस्था का विकास करने की आवश्यकता को देखते हुए कृतिक बल ने मुख्य रूप से घड़ियों के पुर्जों का निर्माण करने हेतु कुछ बड़े एककों को जिनमें से प्रत्येक की वार्षिक क्षमता 12 लाख होगी स्थापना करने की सिफारिश की है। ये बड़े एकक पोषक एकक के रूप में कार्य करेंगे जो लघु तथा मध्यम एककों को अपने ब्रान्ड नाम से पुर्जे जोड़ कर तथा विपणन करने के लिये घड़ियों के उत्पादन के कम से कम दो तिहाई पुर्जों की सप्लाई कर सकेंगे सरकार कृतिक बल की सिफारिशों पर विचार करते हुए यांत्रिक घड़ियां बनाने के लिये एक नयी नीति बना रही है।

मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्टरी की स्थापना

4506 **श्री जैनुल बशर** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत कई वर्षों से अनुभव की जा रही सीमेंट की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र में सीमेंट की फैक्टरी की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) यदि हां तो क्या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जहां सीमेंट के उत्पादन के लिये अपेक्षित कच्चामाल उपलब्ध है, सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां तो क्या वहां सीमेंट फैक्टरी की स्थापना का कोई विचार है और यदि हां, तो वहां कब तक फैक्टरी स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) भारतीय सीमेंट निगम और राज्य औद्योगिक निगम सरकारी क्षेत्र में सीमेंट की अतिरिक्त क्षमता स्थापित कर रहे हैं।

(ख) भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण व राज्य भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग आदि द्वारा की गई जांच के अनुसार मिर्जापुर जिले में अनुमानित श्रेणी के अंतर्गत लगभग 1850 लाख मी० टन सीमेंट ग्रेड के चूने के पत्थर का कुल भंडार उपलब्ध है;

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक सीमेंट कारखाना स्थापित कर रहा है। यह परियोजना दो चरणों में क्रियान्वित की जा रही है तथा दोनों चरणों के वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

प्रत्येक 1000 व्यक्तियों के लिये पुलिसमैनों की संख्या

4507 **श्री जैनुल बशर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक 1000 की जनसंख्या के पीछे कितने पुलिसमैन हैं और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार की नीति के अनुसार, प्रत्येक 1000 की जनसंख्या के पीछे कितने पुलिसमैन होने चाहिये ;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में राज्यों को कोई सलाह दी है ; और

(घ) क्या राज्यों की वित्तीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिये राज्यों को कोई वित्तीय सहायता देने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सातवें वित्त आयोग ने असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में वर्ष 1979-84 की अवधि में पुलिस प्रशासन के स्तर को उन्नत करने के लिए 168.73 करोड़ रुपये राजस्व व्यय की सिफारिश की है। राजस्व व्यय में वृद्धि करने के ये उपबन्ध इन राज्यों को पुलिस प्रशासन के मामले में पिछड़े हुए हैं को सक्षम करने के साथ-साथ सिविल पुलिस की संख्या में वृद्धि करने में समर्थ करेंगे।